Advisory Committee meetings from time to time and States have been apprised of the need for immediate settlement of disputed claims and early payment of outstanding dues to the Government of Gujarat, in terms of Narmada Water Dispute Tribunal Award.

Srisailam Left Bauk Canal Project, Andhra Pradesh

1560. DR. G. VIJAY MOHAN REDDY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government have given clearance to Srisailam Left Bank canal project in Adhra Prakesh ;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The project after its examination in Central Water Commission was sent back to the State Government in June, 1987 to clearly establish the water availability on long term basis as the Krishna Water Disputes Tribunal has not allocated any water for this project. The Government of Andhra Pradesh has based its report on surplus Krishna river waters, availability of which is open for review after 2000 A.D.

Chambal Phase-II Project Rajasthan

1561. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chambal CAD Phase-II Project which was submitted by Rajasthan Government to the Central Government in the year 1987 is still pending for clearance;

(b) what is the present position of the project ; and

(c) when the project was passed on to the World Bank through the concerned Deptt. for obtaining finance and if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The project has been examined. Decision on posting the project for exter nal assistance is under process.

Involvement of Private Companies in Irrigation Projects

1562. SHRI SOM PAL : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to involve private companies in major and medium irrigation projects ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) what are the modalities of the schemes ; and

(d) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d) There is no proposal for privatisation of major and medium irrigation projects which are capital intensive. But the work of maintenance of system and distribution of water at the tertiary level and recovery of water-rates is proposed to be entrusted to the water users associations and cooperatives.

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

1563. **श्री रणजीत सिंह :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि कितनी है और जनवरी, 1992 तक वास्तव में इन्हें कितनी धनराशि अदा की गई थी ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्यों को धन आबंटित करने के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । स्प्रिंकलर/ड्रिप प्रणाली आदि के प्रयोग को बढ़ावा देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली के वास्ते राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा शुष्क क्षेत्र में फलों के समेकित विकास पर केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के वास्ते चालू वर्ष के दौरान 1652 लाख रुपए का कुल आबंटन किया गया है ।

(ख) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन, राज्य बजट में बराबर का आबंटन प्रदान करके निधियों का उपयोग करने के लिए, लघु, सीमान्त तथा अन्य कृषकों के वास्ते आर्थिक सहायता की दरों, किसी विशेष राज्य के लिए स्कीम के महत्व, तैयारी कर स्तर, अवसंरचना की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता हेतु उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर होता है ।

विवरण

राज्यों के नाम और प्रत्येक को आबंटित और निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1991-92 के दौरान अनुमोदित/ आबंटित की गयी राशि	वर्ष 1991-92 के दौरान निर्मुक्त की गयी राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	110.86	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.12	1.00
3.	असम	5.00	1.00
4.	बिहार	30.00	10.00
5.	गुजरात	200.04	55.04
6.	गोआ	5.00	1.00
7.	हरियाणा	5.00	1.00
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00	25.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30.00	10.00
10.	कर्नाटक	50.00	15.00
11.	केरल	80.00	20.00
12.	मध्य प्रदेश	100.00	27.00
13.	महाराष्ट्र	508.58	208.58
14.	मणिपुर	5.00	1.00
15.	मेघालय	5.00	1.00

1	2	3	4
16.	मिजोरम	5.00	1.00
17.	नागालैण्ड	5.00	1.00
18.	उड़ीसा	25.00	10.00
19.	पंजाब	80.00	20.00
20.	राजस्थान	70.00	20.00
21.	सिक्किम	5.00	1.00
22.	तमिलनाडु	100.00	25.00
23.	त्रिपुरा	5.00	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	120.00	30.00
25.	पश्चिम बंगाल	5.00	1.00
26.	पांडिचेरी	5.00	—
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.00	—
	कुल	1652.60	506.62

Linking of Brahmaputra with peninsular Rivers

1564. SHRI KAPILVERMA : SHRIMATI SATYA BAHIN: SHRIMATI VEENA VERMA : SHRI SARADA MOHANTY: SHRI CHIMANBHAI MEHTA: SHRI RAM AWADHESH SINGH :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government are considering any plan for linking the Brahmaputra in Assam withGanga and peninsular rivers like Mehandi in Orissa and Godavari and Krishna inAndhra Pradesh;

(b) what are the deails thereof with cost involved, time and power irrigation potential likely to be created as a result thereof ; and

(c) the financial outlay of this project and period for completion ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A National Perspective for Water Resources Development prepared by the Government, among other links, envisages inter-linkages between Brahmaputra-Ganga-Mahanadi National Water Development Agencyfhas confined the studies to the assessment of water availability in brahmaputra and its tributaries, namely, Manas and Bankosh to determine the quantum of surplus water available for transfer and topo sheet examination of links and reservoirs. The National Water Development Agency has separately carried out preliminary feasibility studies for interlining Mahanadi Godavari and Krishna under the peninsular Component.

(b) and (c) In the absence of detailed project reports, aspects like cost involved, benefits envisaged, outlay: required and completion schedule cannot be quantified.

1565. [*Transferred to the 16th March*, 1992]

1566. [*Transferred to the 16th March*, 1992]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

1567. डा० अबरार अहमद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच के लिए राज्यों में कोई समितियां हैं और यदि हां, तो राजस्थान के बारे में इन समितियों का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) इस कार्यक्रम की जांच के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर क्या व्यवस्था है ; क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समिति है